

भारत के आर्थिक विकास में बैंकों की भूमिका: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

SHAINOO RAM SORI

RESEARCH SCHOLAR (DEPARTMENT OF ECONOMICS)

सार

बैंक बचत को जुटाकर, ऋण प्रदान करके और विभिन्न क्षेत्रों में वित्तीय लेनदेन को सुविधाजनक बनाकर भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे बचतकर्ताओं और निवेशकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं, औद्योगिक विकास, कृषि विकास और बुनियादी ढाँचे के विस्तार के लिए कुशल पूंजी आवंटन सुनिश्चित करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक शहरी और ग्रामीण आबादी को वित्तीय सेवाएँ प्रदान करके समावेशी विकास में योगदान करते हैं। वित्तीय समावेशन पहल, डिजिटल बैंकिंग और प्रधानमंत्री जन धन योजना जैसी सरकारी योजनाओं की शुरुआत ने आर्थिक प्रगति पर बैंकिंग क्षेत्र के प्रभाव को और मजबूत किया है। बैंक ऋण सुविधाओं के माध्यम से छोटे और मध्यम उद्यमों (एसएमई), स्टार्टअप और बड़े पैमाने के उद्योगों का भी समर्थन करते हैं, जिससे रोजगार सृजन और उद्यमिता को बढ़ावा मिलता है। इसके अतिरिक्त, वे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने, वित्तीय प्रणाली को स्थिर करने और हरित बैंकिंग पहलों के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह विश्लेषणात्मक अध्ययन भारत के आर्थिक विकास में बैंकों के बहुमुखी योगदान की जांच करता है, पूंजी निर्माण, वित्तीय समावेशन और नीति कार्यान्वयन में उनकी भूमिका की खोज करता है जबकि गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) और नियामक बाधाओं जैसी चुनौतियों का समाधान करता है।

मुख्य शब्द:- आर्थिक विकास; आर्थिक विकास; प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद; बैंकिंग क्षेत्र; भारत।

परिचय

वित्तीय संस्थाओं का लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ाने में कई तरह से महत्वपूर्ण योगदान है। आर्थिक विकास किसी देश की कुशल वित्तीय संस्थाओं पर निर्भर करता है। इसलिए, वित्तीय विकास वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ाने के लिए उपयोगी है, इस प्रकार यह किसी देश की आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने में प्रभावी भूमिका निभाता है। बैंकिंग एक वित्तीय संगठन है जो ऋणदाताओं और लेनदारों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। बैंकिंग क्षेत्र जमा को उत्पादक निवेश में बदलने, नई पूंजी बनाने और आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए उपयोगी है। यह भी वैचारिक रूप से सिद्ध है कि किसी अर्थव्यवस्था का समग्र विकास बैंकिंग क्षेत्र के उचित स्वास्थ्य से महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। बैंकिंग क्षेत्र कई गतिविधियाँ करता है जैसे कि व्यक्तिगत और व्यावसायिक समुदाय से जमा स्वीकार करना और आम लोगों और व्यावसायिक समुदाय को ऋण प्रदान करना। चूंकि बैंकिंग क्षेत्र आम नागरिकों की छोटी बचत को स्वीकार करता है और आम लोगों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए ऋण प्रदान करता है। इसके अलावा, बैंकिंग संस्थान लोगों को अपनी छोटी बचत बैंकों में जमा करने के लिए प्रेरित करता है। बैंकिंग संस्थान सभी क्षेत्रों में व्यावसायिक समुदाय को अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक ऋण भी प्रदान करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह व्यावसायिक समुदाय और कृषक समुदाय को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह उद्योग और कृषि क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करता है। इसके बाद, अर्थव्यवस्था में बैंकिंग क्षेत्र

की भूमिका बढ़ने के साथ वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि होने की उम्मीद है। इसलिए, बैंकिंग संस्थान धन प्रवाह को बनाए रखने और अर्थव्यवस्था में भौतिक संपत्ति बनाने में योगदान करने में सहायक है। बैंकिंग क्षेत्र दक्षता संचालित करने, वित्तीय प्रणाली में स्थिरता प्रदान करने और जनता को आसान, सुरक्षित और वित्तपोषण प्रदान करके समान आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए भी प्रभावी है, यह देश में पूंजी निर्माण का मार्ग भी तैयार करता है। नतीजतन, बैंकिंग क्षेत्र का किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है, लोगों ने तर्क दिया है कि बैंकिंग क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुमार (2019) ने इस बात पर प्रकाश डाला कि किसी राष्ट्र की आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने में बैंकिंग क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाटिया और महेंद्र (2015) ने तर्क दिया है कि कुशल बैंकिंग प्रणाली आर्थिक विकास में योगदान करती है। बैंकिंग क्षेत्र की कुशल दक्षता आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए बचत और जमा निधियों के जुटाव को बढ़ाने में सहायक है। दावा किया गया कि कुशल बैंकिंग क्षेत्र वित्तीय बचत के जुटाव के माध्यम से आर्थिक विकास को मजबूत करने और भौतिक संपत्ति बनाने के लिए इन बचत का उपयोग करने के लिए महत्वपूर्ण चालक के रूप में काम करता है।

भारत में बैंकिंग प्रणाली की स्थापना 18वीं शताब्दी में हुई थी, जिसमें जनरल बैंक ऑफ़ इंडिया की स्थापना 1786 में हुई थी और सबसे पुराना बैंक स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया की स्थापना 1806 में हुई थी। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) का राष्ट्रीयकरण 01 अप्रैल 1935 को किया गया था। समय के साथ, 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और चार अन्य को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में मिला दिया गया। RBI बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित और विनियमित करता है, जिसे मोटे तौर पर अनुसूचित और गैर-अनुसूचित बैंकों में वर्गीकृत किया जाता है। अनुसूचित बैंकों में RBI अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची के तहत सूचीबद्ध सभी सहकारी या वाणिज्यिक बैंक शामिल हैं, जबकि सहकारी बैंक सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं। वाणिज्यिक बैंकों को आगे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में विभाजित किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सरकारी स्वामित्व वाले उद्यम हैं, जिनमें से 12 बैंक वर्तमान में भारत में काम कर रहे हैं और हाल ही में उनकी बैलेंस शीट को मजबूत करने के लिए विलय किए गए हैं। निजी क्षेत्र के बैंक निजी स्वामित्व वाले होते हैं, उदाहरण के लिए ICICI बैंक और एक्सिस बैंक निजी स्वामित्व के तहत काम कर रहे हैं। विदेशी बैंक RBI से अपेक्षित बैंकिंग लाइसेंस के आधार पर भारत में पंजीकृत हैं। भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर बैंकिंग पहुँच बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की। भारत में छोटे वित्त बैंक और भुगतान बैंक हैं, छोटे वित्त बैंक उन क्षेत्रों की सेवा करते हैं जहाँ पारंपरिक बैंक नहीं पहुँच सकते हैं और स्थानीय आबादी को सेवाएँ प्रदान करते हैं, जबकि भुगतान बैंक भुगतान और प्रेषण की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए निर्बाध वित्तीय लेनदेन सुनिश्चित होता है।

उद्देश्य

1. इसका अध्ययन करना कि किस प्रकार वाणिज्यिक बैंक कृषि, उद्योग और सेवाओं को ऋण और वित्तीय सेवाएँ प्रदान करके भारत में आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं।
2. जांच करें कि सरकारी नीतियाँ और बैंकिंग सुधार किस प्रकार वंचित समुदायों के वित्तीय समावेशन और ग्रामीण एवं शहरी भारत में सतत आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं।

साहित्य की समीक्षा

बैंकिंग क्षेत्र और आर्थिक विकास

बैंकिंग क्षेत्र कई तरीकों से आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। यह खंड एक राष्ट्र की विभिन्न गतिविधियों में बैंकिंग क्षेत्र की भूमिका प्रदान करता है। बैंकिंग क्षेत्र लोगों की बचत की आदतों को बढ़ावा देने के लिए बैंकों में जमा करने के लिए अनुकूल है ताकि उन्हें बेहतर और सुरक्षित रिटर्न मिल सके (मुनिस्वामी, 2018)। पूंजी निर्माण एक राष्ट्र के लिए रक्त के रूप में कार्य करता है। चूंकि बैंकिंग क्षेत्र जमाकर्ताओं से जमा राशि एकत्र करता है और एकत्रित राशि लोगों, व्यापारिक समुदाय, किसानों और अन्य लोगों को लाभ कमाने के लिए ऋण के रूप में प्रदान करता है। इस प्रकार, पूंजी निर्माण करने के लिए बैंकिंग क्षेत्र अत्यधिक प्रभावी है (मुनिस्वामी, 2018)। बैंकिंग संस्थान व्यवसाय समुदाय को नए उद्योग और उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान करते हैं (सिंह एट अल., 2019; सिंह एट अल., 2020)। उपयुक्त बैंकिंग क्षेत्र मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और अन्य के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार के लिए धन हस्तांतरण करने के लिए उपयोगी है (मुनिस्वामी, 2018)। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास काफी हद तक कृषि क्षेत्र पर निर्भर करता है क्योंकि यह क्षेत्र भारतीयों की खाद्य सुरक्षा को पूरा करता है। बैंकिंग क्षेत्र किसानों को उनकी कृषि गतिविधियों के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है। इसके बाद, बैंकिंग क्षेत्र कृषि उत्पादन को बढ़ावा देता है (कुमार एट अल., 2017; सिंह एंड ज्योति, 2021)। चूंकि बैंकिंग क्षेत्र उद्योग और व्यापार समुदाय को ऋण प्रदान करता है। इसलिए, यह बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करता है (मुनिस्वामी, 2018)। मुद्रास्फीति, अपस्फीति और संकट के कारण आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

बैंकिंग क्षेत्र और आर्थिक विकास संघ

वर्तमान में बैंकिंग क्षेत्र भारत के सबसे बड़े सेवा प्रदाता क्षेत्रों में से एक है (कुमारी, 2017)। भारत में, बैंकिंग क्षेत्र क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम सेवाएं, टेलीबैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, उपभोक्ता वित्त, जीवन बीमा, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, विनियमन सेवाएं, स्टॉक ब्रोकिंग सेवाएं (कुमारी, 2017; मुनीस्वामी, 2018) जैसी कई सेवाएं प्रदान कर रहा है। तदनुसार, आर्थिक विकास को बढ़ाने में बैंकिंग क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। पिछले अध्ययनों ने सैद्धांतिक और अनुभवजन्य रूप से साबित किया है कि बैंकिंग क्षेत्र का आर्थिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, मुनीस्वामी (2018) ने भारत में पूंजी निर्माण और आर्थिक विकास में बैंकों की भूमिका का आकलन किया। आलम एट अल. (2021) ने बताया है कि बैंकिंग क्षेत्र के ब्याज मार्जिन और संपत्ति पर रिटर्न का भारत में आर्थिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। (2018) ने दावा किया है कि वाणिज्यिक बैंक वित्तीय प्रणाली पर हावी हैं और आर्थिक विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। हालांकि, पिछले अध्ययनों में आर्थिक विकास और बैंकिंग क्षेत्र के बीच एक समान संबंध नहीं पाया जा सका। सईद एट अल. (2018) ने पाकिस्तान में बैंकिंग क्षेत्र और आर्थिक विकास के बीच सकारात्मक द्वि-दिशात्मक कार्य-कारण संबंध की सूचना दी। जोशी (2017) ने भारत में वित्तीय विकास और विकास के बीच संबंधों का आकलन किया।

अनुसंधान क्रियाविधि

यहां शोधकर्ता ने प्रदर्शन के विश्लेषण के लिए द्वितीयक डेटा का उपयोग किया है और प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए जमा, निवेश, ऋण और अग्रिम, उधार, अचल संपत्ति और अन्य संपत्ति जैसे घटकों के रूप में उपयोग किया है। शोधकर्ता ने केवल सरल यादृच्छिक नमूने के आधार पर 3 बैंकों का चयन किया है क्योंकि ज्यादातर ये तीन बैंक वित्तीय सहायक में प्रदर्शन कर रहे हैं। यह शोध पूरी तरह से द्वितीयक डेटा पर आधारित है जो बैंकों की वार्षिक

रिपोर्ट से एकत्र किया गया था और अध्ययन की अवधि 2014-15 से 2019-2020 तक छह साल है, यह मेरे शोध कार्य को सामान्यीकृत कर सकता है ताकि शोधकर्ता ने छह साल का चयन किया हो। शोधकर्ता विभिन्न घटकों के आधार पर प्रदर्शन जानना चाहते हैं जो जमा, निवेश, ऋण और अग्रिम, उधार, अचल संपत्ति और अन्य संपत्ति हैं

परिणाम और चर्चा

खोज का अर्थ है शोध के परिणामस्वरूप खोजी गई जानकारी। यह शोध पूरी तरह से द्वितीयक डेटा पर आधारित है और विभिन्न पुस्तकों, पत्रिकाओं, वेबसाइटों और चयनित विकास बैंकों की छह साल की वार्षिक रिपोर्टों से एकत्र किए गए डेटा पर भी आधारित है। डेटा के विश्लेषण के लिए शोधकर्ता प्रवृत्ति विश्लेषण और एनोवा परीक्षण शामिल करता है। डेटा के संग्रह के लिए, शोधकर्ताओं के लिए डेटा एकत्र करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि कई विकास बैंकों की अपनी उप-शाखाएँ होती हैं, इसलिए यह तय करना कि शोध के लिए किस विकास बैंक का चयन किया जाए, बैंकों का चयन करने के बाद डेटा की गणना करना मुश्किल हो जाता है। ये शोध द्वितीयक डेटा पर आधारित हैं और निम्नलिखित परिणाम निकालते हैं।

तालिका 1. एनोवा के आधार पर परिणाम की गणना

विवरण	गणना मूल्य	तालिका मान
जमा	8.4921	3.6823
निवेश	0.5733	3.6823
ऋण और अग्रिम	0.9329	3.6823
उधारी	3.3353	3.6823
अचल संपत्तियां	0.9947	3.6823
अन्य परिसंपत्तियां	2.1383	3.6823

दिए गए डेटा में जमा, निवेश, ऋण और अग्रिम, उधार, अचल संपत्ति और अन्य संपत्तियों जैसे विभिन्न वित्तीय मापदंडों के लिए गणना किए गए मूल्यों और तालिका मूल्यों के बीच तुलना प्रस्तुत की गई है। 3.6823 का तालिका मूल्य तुलना के लिए एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है, जो यह निर्धारित करने में मदद करता है कि प्रत्येक गणना मूल्य महत्वपूर्ण है या नहीं। यदि गणना किया गया मान तालिका मूल्य से अधिक है, तो यह सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण विचलन को इंगित करता है, जबकि यदि यह कम है, तो भिन्नता पर्याप्त नहीं हो सकती है।

जमाराशियों के मामले में, 8.4921 का परिकलित मूल्य तालिका मूल्य से काफी अधिक है, जो यह दर्शाता है कि जमाराशियाँ अपेक्षित मानक से काफी विचलन दर्शाती हैं। यह विश्लेषण के तहत वित्तीय संस्थान के भीतर जमा पैटर्न में एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति या परिवर्तन का संकेत दे सकता है। इसके विपरीत, निवेश का परिकलित मूल्य

0.5733 है, जिसका अर्थ है कि यह पर्याप्त भिन्नता प्रदर्शित नहीं करता है और तालिका मूल्य की तुलना में स्थिर सीमा के भीतर रहता है।

ऋण और अग्रिम, उधार और अचल संपत्तियों ने क्रमशः 0.9329, 3.3353 और 0.9947 के मूल्यों की गणना की है। तीनों मान तालिका मूल्य से नीचे हैं, जो दर्शाता है कि उनके बदलाव सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नहीं हैं। हालाँकि, उधार तालिका मूल्य के बहुत करीब हैं, जो एक मामूली विचलन का संकेत दे सकता है जो आगे की जांच के लायक हो सकता है। अचल संपत्ति और ऋण और अग्रिम, अपेक्षाकृत कम होने के कारण, सुझाव देते हैं कि ये घटक वित्तीय प्रदर्शन में स्थिर रहते हैं।

अन्य परिसंपत्तियों का परिकलित मूल्य 2.1383 है, जो तालिका मूल्य से भी कम है, जो दर्शाता है कि इस श्रेणी में उतार-चढ़ाव बहुत महत्वपूर्ण नहीं हैं। प्रदान किए गए मूल्यों के समग्र विश्लेषण से पता चलता है कि जमाराशियाँ पर्याप्त विचलन दिखाती हैं, जबकि अन्य वित्तीय पैरामीटर अपेक्षाकृत स्थिर रहते हैं। यह जानकारी वित्तीय निर्णय लेने, जोखिम मूल्यांकन और बेहतर संसाधन आवंटन के लिए रणनीतिक योजना बनाने में उपयोगी हो सकती है।

तालिका 2. सुझावों के लिए मूल्यांकन

घटक बैंक	सिडबी	नाबार्ड	एग्जिम
औसत जमा	2,01,31,93,47,507.3	17,74,35,36,52,666.7	17,04,19,86,443.7
रैंक	दूसरा	पहला	तीसरा
औसत निवेश	55,22,78,72,330	2,40,27,43,60,000	45,91,96,74,869
रैंक	दूसरा	पहला	तीसरा
औसत ऋण और अग्रिम	6,69,80,91,11,289.5	26,02,20,84,71,500	8,77,56,17,96,852
रैंक	तीसरा	पहला	दूसरा
उधार का औसत	3,80,91,46,05,752	1,89,44,61,28,833.3	1,49,03,37,20,797.3
रैंक	पहला	दूसरा	तीसरा
औसत अचल संपत्ति	2,09,31,69,110.333	3,63,40,37,166.7	1,04,72,44,255.667
रैंक	तीसरा	पहला	दूसरा
औसत अन्य परिसंपत्तियाँ	19,32,59,21,410	42,05,18,29,339	46,38,63,69,609.5
रैंक	तीसरा	दूसरा	पहला

नाबार्ड में विभिन्न प्रकार की जमाराशि शामिल हैं, तथा यह अन्य बैंकों की तुलना में जमाराशि का उच्च रुझान दर्शाता है। इसलिए, तीन बैंकों को अपनी जमाराशि बनाए रखने तथा ऋण और अग्रिम के क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया गया है। यहां, सिडबी और एक्जिम के लिए उन्हें अन्य विकल्पों में निवेश करना होगा, ताकि उन्हें अधिक प्रतिफल मिल सके। चूंकि निवेश बैंकों के विकास में उपयोगी भूमिका निभाता है, इसलिए ऋण और अग्रिम का अनुपात बढ़ाएं, क्योंकि इससे जमाराशि की तुलना में अधिक प्रतिफल मिलता है। जमाराशि की तुलना में अधिक ऋण और अग्रिम प्रदान करना तथा उच्च ब्याज दर लेना अच्छा है। इसलिए, तीनों बैंकों को ऋण और अग्रिम प्रदान करने की उच्च राशि बढ़ानी होगी। जब बैंक, कंपनियां कहीं से उधार लेती हैं, तो यह विशेष बैंकों के लिए देयताएं होती हैं। इसलिए, सिडबी को अपनी उधारी कम करनी होगी। जमाराशि लेने के विकल्प उधार लेने की तुलना में कम खर्चीले हैं। अनावश्यक अचल संपत्तियों को कम करके। विस्तार, नई परियोजनाओं और विकास के लिए बैंकों में पूंजी निवेश करना बेहतर था। नाबार्ड में अचल संपत्तियां अधिक हैं। इसलिए, उन्हें अन्य संपत्तियों का उचित उपयोग करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक बैंक के लिए अन्य संपत्तियों का रखरखाव एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए, विस्तार और विकास के लिए इसे बनाए रखना आवश्यक है।

निष्कर्ष

भारत के आर्थिक विकास में बैंकों की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ऋण प्रवाह को सुगम बनाते हैं, जिससे कृषि, उद्योग और सेवाओं में वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। वित्तीय समावेशन में बैंकिंग क्षेत्र की भागीदारी ने ग्रामीण और शहरी आबादी के बीच की खाई को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे उन्हें आवश्यक वित्तीय संसाधनों तक पहुँच प्रदान करने में सशक्त बनाया गया है। सरकारी नीतियों और सुधारों ने बैंकिंग प्रणाली को और मजबूत किया है, जिससे बेहतर सेवा वितरण, पारदर्शिता और वित्तीय साक्षरता सुनिश्चित हुई है। हालाँकि, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) जैसी चुनौतियों का समाधान करने और समावेशी और सतत आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए बैंकिंग सेवाओं की पहुँच को और अधिक दूरदराज के क्षेत्रों तक बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है।

संदर्भ

1. मुनिस्वामी डी. (2018). आर्थिक विकास में वाणिज्यिक बैंकों की भूमिका: भारतीय परिप्रेक्ष्य. आईजेआरएआर, 5(1):645-649.
2. सिंह ए.के. और ज्योति बी. (2020)। भारत के चयनित विनिर्माण उद्योगों में फर्म के वार्षिक कारोबार को प्रभावित करने वाले कारक: एक अनुभवजन्य अध्ययन। बिजनेस पर्सपेक्टिव रिव्यू, 2(3):33-59।
3. सिंह ए.के., आर्य ए. और अशरफ एस.एन. (2019)। एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक, व्यावसायिक, बौद्धिक संपदा अधिकार और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी गतिविधियों पर एक वैचारिक समीक्षा। जेएनएनसीई जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, 3(2):1-22।
4. सिंह ए.के. और अशरफ एस.एन. (2020)। चयनित देशों में आर्थिक विकास के साथ उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र का संबंध: एक अनुभवजन्य अन्वेषण। जर्नल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, 8(2):36-92।

5. कुमार ए., अहमद एम.एम. और शर्मा पी. (2017)। भारत में सतत खाद्य सुरक्षा पर जलवायु और गैर-जलवायु कारकों का प्रभाव: एक सांख्यिकीय जांच। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेटिक्स, 3(1):1-30।
6. कुमारी जे. (2017). भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में बैंक की भूमिका. इंपीरियल जर्नल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, 3(1):740-743.
7. आलम, एम.डी.एस., रब्बानी एम.आर., तौसिफ एम.आर. और अबे जे. (2021)। भारत में बैंकों का प्रदर्शन और आर्थिक वृद्धि: एक पैनेल सह-एकीकरण विश्लेषण। अर्थव्यवस्थाएँ, 9(38):1-12।
8. अल-होमीदी ईए, तबाश एमआई, फरहान एनएचएस और अलमकतारी एफए (2018)। भारतीय वाणिज्यिक बैंकों की लाभप्रदता के बैंक-विशिष्ट और मैक्रो-इकोनॉमिक निर्धारक: एक पैनेल डेटा दृष्टिकोण। कॉजेंट इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, 6(1):1-26।
9. जोशी एस. (2017). भारत में वित्तीय क्षेत्र का विकास और आर्थिक वृद्धि: कुछ विचार. एमपीआरए पेपर नंबर 81201. <https://mpira.ub.uni-muenchen.de/81201/>.
10. सईद एमवाई, रमज़ान एम. और हामिद के. (2018)। बैंकिंग प्रदर्शन संकेतकों और आर्थिक विकास की गतिशीलता: पाकिस्तान में दीर्घकालिक वित्तीय विकास संबंध। यूरोपियन ऑनलाइन जर्नल ऑफ़ नेचुरल एंड सोशल साइंस, 7(3):141-163।
11. रस्तोगी, शैलेश, और ई. रागबिरुन्था। 2018. वित्तीय समावेशन और सामाजिक आर्थिक विकास: अंतराल और समाधान। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल इकोनॉमिक्स 45: 1122–40।
12. रस्तोगी, शैलेश, अर्पिता शर्मा, चेतन पानसे और वेंकट मृदुला भीमावरपु। 2021. यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI): एक डिजिटल नवाचार और वित्तीय समावेशन और आर्थिक विकास पर इसका प्रभाव। यूनिवर्सल जर्नल ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस 9: 518–30।
13. ओज़िली, पीटरसन के. 2018. वित्तीय समावेशन और स्थिरता पर डिजिटल वित्त का प्रभाव। बोर्सा इस्तांबुल समीक्षा 18: 329–40।
14. किम, मिंजिन, हनाह जू, हीजिन ली और जूही कांग। 2017. मोबाइल, वित्तीय समावेशन और विकास: अकादमिक साहित्य की आलोचनात्मक समीक्षा। ऑनलाइन उपलब्ध: <https://aisel.aisnet.org/globdev2017/4/> (21 अक्टूबर 2022 को एक्सेस किया गया)।
15. इनौए, ताकेशी, और शिगेयुकी हमोरी। 2016. वित्तीय पहुँच और आर्थिक विकास: उप-सहारा अफ्रीका से साक्ष्य। उभरते बाजार वित्त और व्यापार 52: 743–53।
16. कुमार आर. (2019)। बैंकिंग क्षेत्र में डेटा एनवेलपमेंट विश्लेषण के हालिया अनुप्रयोग: एक सर्वेक्षण। इंटरनेशनल जर्नल फॉर रिसर्च इन एप्लाइड साइंस एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, 7(11):449-456।

